भारत में नीलामियों के लिये आरक्षित कीमत के रूप में लिय जाता है, घरेलू बाजार में ऊंची कीमत परिलक्षित होती रही है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न किस्मों की काफी की सापेक्षिक कीमत की स्थिति निम्नलिखित है:

(औसत कीमत प्रति 50 किग्रा–रूपये में)

वर्ष	प्लांट "ए"
1991	1926.50
1992	1698.48
1993	2185.55

अरेब. चाई		रोब. चाई	
क	ख	क	ख
1594.75		1467.25	
1545.31		1308.33	
1806.35		1658.70	

(ङ) काफी का उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :

(1) गहन कृषि स्वरूप को अपनाना;

(2) पुराने तथा मृतप्राय काफी बागानों में नई तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों का पुनर्रोपण करना;

(3) सिचाई व्यवस्थाओं में कारगर सुधार;

(4) काफी बेरी-बोरर पेस्ट तथा अन्य बीमारियों का जैविकीय नियंत्रण ।

निर्यात को बढ़ाने के लिये काफी विपणन को पिछले 50 वर्षों में पहली बार उदार बनाया गया है । ऐसा मुक्त बिक्री कोटा की शुरूआत करके किया गया है जिसके तहत उपजकर्ता अपनी उपज का 50% घरेलू और विदेशी बाजारों में बेच सकता है । काफी बोर्ड भारतीय काफी को लोकप्रिय बनाने के लिये विदेशों में प्रचार अभियान भी चलाता है ।

भारत-नेपाल व्यापार समझौता

1843. **श्री सोमपाल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जून, 1994 के "दि इकोनोमिक टाइम्स" में कुछ लोगों द्वारा भारत-नेपाल व्यापार समझौते का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं । इकोनोमिक टाइम्स के दिनांक 22 जून, 1994 के दिल्ली तथा कलकत्ता संस्करण प्राप्त हुये हैं उनमें भारत नेपाल व्यापार करार के बारे में इस प्रकार का कोई समाचार नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Ratification of GATT by Parliament

1844. SHRI RAMDAS AGARWAL : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether the GATT Agreement is likely to be brought for the approval during the Monsoon Session of the Parliament and whether Government have carefully examined the interests of farmers in the country in the light of GATT agreement on fertilizer subsidy and price structure of fertilizers/pesticides; and

(b) if so, whether Government propose to take all other Political parties/Groups